



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 2013/ कार्तिक 6, 1935

No. 245]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2013/KARTIKA 6, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2013

विषय : दक्षिण अफ्रीका के मूल के या वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णयक समीक्षा।

सं. 15/21/2013—डीजीएडी.— समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीका के मूल के या वहां से निर्यातित फेनोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर 15 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 14/4/2002—डीजीएडी के तह मूल रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। और यतः केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना 47/2003—सी.श., दिनांक 24 मार्च, 2003 जारी की थी।

2. यतः प्राधिकारी ने इस बीच यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा संपन्न की। 6 फरवरी, 2013 की अधिसूचना के तहत यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर से पाटनरोधी शुल्क हटाने की सिफारिश की।

3. यतः मै. हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. (एच ओ सी एल) तथा एस आई ग्रुप इंडिया लि. (जिन्हें याचिकाकर्ता या आवेदन भी कहा गया है) ने सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की सभावना का आरोप लगाते हुए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (प्राधिकारी) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग

4. यह याचिका मै. हिंदुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लि. तथा एस आई ग्रुप इंडिया लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध उत्पाद के एकमात्र उत्पादक हैं। अतः याचिका आधार को पूरा करती है और याचिकाकर्ता नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. मूल जांच, परवर्ती निर्णायक समीक्षा तथा मध्यावधि समीक्षा में और वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन में भी विचाराधीन उत्पाद फेनोल है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

‘‘विचाराधीन उत्पाद सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल का या वहां से निर्यातित फेनोल है। फेनोल एक मूलभूत कार्बनिक रसायन है जो सामान्यतः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। उत्पाद का विपणन दो रूपों – बल्क एवं पैकड रूप में किया जाता है। बल्क बिक्री सामान्यतः खुले रूप में की जाती है जबकि पैकड प्रेषण अत्यंत छोटे कंटेनर भार में और आमतौर पर ड्रमों में पैक कर किया जाता है। फेनोल का उपयोग फेनोल फार्मल्डाइड रेजिन, लेमिनेट्स, प्लाइवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिस्फेनोल – ए, अल्काइल फेनोल्स, भेषज, डाइफिनायल आक्साइड आदि में किया जाता है। यह उत्पाद भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 तथा 2707.60 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क एवं आई टी सी एच एच वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।’’

6. यह एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण जांच में वही उत्पाद शामिल है जो मूल जांच में शामिल था।

7. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता दोनों का अदल-बदलकर उपयोग करते हैं। वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु के ‘समान वस्तु’ माना जा रहा है।

संबद्ध देश

8. वर्तमान आवेदन दक्षिण अफ्रीका (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के आरोपित सतत पाठन के संबंध में दायर किया गया है।

सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं और तदनुसार उन्होंने सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। जांच के बाद प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

10. भारत में आयात की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस से आंकड़े प्राप्त कर निर्यात कीमत निर्धारित की है। ये कीमतें एफ ओ बी निर्यात कीमतें हैं। कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े एवं बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाठनमार्जिन

11. याचिकाकर्ताओं ने इस आशय का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे किसी समीक्षा जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रथमदृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाठन जारी है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल कीमत प्रभाव, जैसा कि कीमत कटौती और कीमत हास से देखा जा सकता है, के रूप में वास्तविक क्षति जारी है जिससे लाभ में नकारात्मक स्तर तक गिरावट आई है, लगाई गई पूँजी पर आय तथा नकद लाभ आदि घटा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सतत वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि किसी समीक्षा जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से सतत पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

पाटनरोधी शुल्क निर्णयक समीक्षा की शुरूआत

13. उपर्युक्त सूचना और दायर किए गए विधिवत पुष्टीकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी इस बात की जांच करने कि क्या उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए एतदद्वारा निर्णयक समीक्षा जांच शुरू करते हैं ।

जांच अवधि

14. वर्तमान निर्णयक समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 (12 माह) तक की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2009, 2010, 2010, 2011, 2011–2012 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल होगी ।

प्रक्रिया

15. इस जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को निरंतर लागू रखना आवश्यक है, क्या शुल्क समाप्त या परिवर्तित किए जाने, या दोनों ही स्थितियों में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

(क) जहां तक दक्षिण अफ़्रीका का संबंध है, इस समीक्षा में दिनांक 15 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 14/4/2003—डीजीएडी (मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम) और परवर्ती समीक्षा अधिसूचनाओं के सभी पहलू शामिल हैं ।

(ख) इस जांच में शामिल देश दक्षिण अफ़्रीका है ।

(ग) उपर्युक्त पाटनरोधी नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग,

कमरा सं. 243, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है ।

समय—सीमा

18. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग—अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए ।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए खतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है ।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है ।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं । संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे.एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2013

Subject: Sunset review of Anti Dumping Duty imposed in respect of imports of Phenol originating in or exported from South Africa.

No No.15/21/2013-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (herein after referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally recommended vide notification No. 14/4/2002- DGAD dated 15th February, 2003 on import of Phenol (hereinafter referred to as

the subject goods) originating in or exported from South Africa and whereas the Central Government issued its Notification 47/2003 - Customs, dated 24th March, 2003.

2. Whereas, the Designated Authority, in the meantime, concluded midterm review investigation against imports of subject goods from European Union, South Africa and Singapore and has vide Notification dated 6th February, 2013 recommended withdrawal of anti dumping duty from subject goods originating in or exported from European Union and Singapore.

3. And whereas, M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) and SI Group India Ltd (also referred to as petitioners or applicants) have jointly filed an application in accordance with the Act and the AD Rules before the Designated Authority (Authority) alleging likelihood of continuation of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countrys and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic industry

4. The petition has been jointly filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and SI Group India Ltd. It is noted that the Petitioners are the only producers of product concern in India. Petition therefore, satisfies the standing and petitioners constitute Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article

5. The Product under consideration, as in the original investigation, subsequent sunset review and mid term review as also in the present sunset review application is Phenol. As per the original investigation carried out by the Designated Authority the product has been defined as under.

"The product under consideration is Phenol originating in or exported from Singapore, South Africa and European Union. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms – bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.60 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."

6. This being a Sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original investigation

7. The petitioners have claimed that the product produced by them is a like article to the product imported from the subject country in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers use the two interchangeably. Subject goods produced by the petitioners are being treated as 'like article' to the goods being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation.

Subject Country

8. The present application has been filed in respect of alleged continued dumping of the product under consideration from South Africa (hereinafter also referred to as subject country).

Normal value

9. The Petitioners have submitted that they were able to get the information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject country and accordingly determined the normal value. The Authority, after examination, has considered the normal value of subject goods in subject country as made available by the applicants.

Export Price

10. Petitioners have determined export price by procuring data from DGCI&S to assess the volume and value of imports in India. These prices are FOB export prices. Price adjustments have been made on account of commission, port expenses, inland freight, and bank charges.

Dumping Margin

11. Petitioners have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, *prima-facie*, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country continue to be dumped, to justify initiation of a review investigation.

Injury and Causal Link

12. The petitioners have claimed that domestic industry continues to suffer material injury by way of adverse price effects as evidenced by price undercutting and price suppression leading to deterioration in profits to negative levels, decline in return on capital employed and cash profits, etc. The petitioners have claimed that the continued material injury has been caused due to the dumped imports from the subject country. The Authority considers that there is sufficient *prima facie* evidence of continued injury caused to the domestic industry by continued dumped imports from subject country to justify initiation of a review investigation.

Initiation of Sunset Review of Anti Dumping Duty

13. In view of the above information and the duly substantiated application filed, and in accordance with Section 9 A (5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation to examine whether expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation:

14. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April 2012 to 31st March 2013 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2009-10, 2010-11, 2011-12 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

15. The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury is likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- a) The review covers all aspects of Notification No. 14/4/2002- DGAD dated 15th February, 2003 (final findings of the original investigation) and subsequent review notifications in so far as they pertain to South Africa.
- b) The country involved in this investigation is South Africa.
- c) Provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Anti-Dumping Rules supra shall be mutatis mutandis applied in this review.

Submission of Information

16. The known exporters in the subject countries, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.243, Udyog Bhawan,
New Delhi-110011.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit:

18. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this review investigation.

Submission of information on confidential basis.

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority